भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 641

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

कोल्लम में ग्रीनफील्ड हाईवे

641. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एनएच 744 ग्रीनफील्ड हाईवे कदम्बट्टुकोणम-एडमोन के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्रवाई शुरू की है, और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एनएच 744 ग्रीनफील्ड हाईवे और उसके शेष हिस्से के विकास कार्य को मंजूरी दी है, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पहले प्रस्तावित विकास के संबंध में एनएच 744 के संरेखण को बदलने का विचार कर रही है, और यदि हां, तो परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि एनएच 77 के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में मुआवजा वितरण में देरी से भूमि मालिकों को कठिनाई हो रही है, और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रीनफील्ड हाईवे सहित कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एनएच 744 के विकास की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) एनएच-744 के कदंबट्टुकोणम-एडमोन खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। डीपीआर के भाग के रूप में, भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार किया जाता है और मुआवजा एनएच अधिनियम 1956 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है जैसा कि लागू होता है।

एनएच-744 के लिए कदंबट्टुकोणम-एडमोन खंड में मदवूर, अयिरनल्लूर और एडमोन गांवों में संरेखण की समीक्षा की जा रही है क्योंकि वन विभाग, केरल सरकार ने दो गांवों (अयिरनल्लूर और एडमोन) में वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इन गांवों में भूमि अधिग्रहण केवल संशोधित संरेखण पर वन विभाग की सहमति के बाद ही आगे बढ़ सकता है।

****